

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा नीलाम किये गये असम्बद्ध और लावारिश बुक किये गये परेषणों / पैकेजों तथा खोई सम्पत्ति गत वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य नीचे की तालिका में दिया गया है :—

वर्ष	नीलाम किये गये परेषणों/ पैकेजों की संख्या	वसूल की गई रकम (लाख रुपयों में)
1978-79	1,93,885	80.63
1979-80	2,16,528	90.32
1980-81	2,86,107	138.82

चूँकि माल अलग-अलग ब्यौरे और किस्म के थे, अतः इतनी बड़ी संख्या में रहने वाले परेषणों / पैकेजों का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

(ख) सभी भारतीय रेलों पर बुक किये गये असम्बद्ध और लावारिश परेषणों / पैकेजों तथा खोई सम्पत्ति वस्तुओं की संख्या 31-12-1981 को 45,005 थी जिनकी नीलामी नहीं की गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

#### Oil Jetty at Sagar Island in West Bengal

3002. SHRI MATILAL HASDA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(1) whether Government have taken any decision for construction of a new oil jetty at Sagar Island in West Bengal;

(b) if so, details thereof;

(c) if not, the reasons for the delay; and

(d) how long will it take for a decision in this regard?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) and (d). It is proposed to locate the second oil jetty near the existing oil jetty at Haldia. Consultants are being appointed to prepare a detailed project report, on receipt of which the matter will be processed for an investment decision.

#### Solution of Kampuchean Problem

3004. SHR R. P. GAEKWAD:  
SHRI CHITTA MAHATA:  
SHRI S. M. KRISHNA:  
SHRI CHINTAMANI JENA:  
SHRI R. L. BHATIA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during his recent visit to Thailand and Vietnam discussions took place on the Kampuchean issue;

(b) whether any principles were determined on which a solution to the Kampuchean issue could be found;

(c) whether India played any specific role in resolving the issue; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) to (d). Yes, Sir. The problems of South East Asia, and especially those of Kampuchea, are a matter of much concern to the coun-

tries in that region. India also desires that South East Asia should become an area free of tensions. During my visit to Vietnam and Thailand, discussions did take place on the situation in South East Asia and the recent developments in that area.

India has put forward no specific proposal or suggestion to resolve the differences. But the discussions were helpful in creating a better appreciation and understanding of the issues involved and of different view points.

### भारतीयों द्वारा बर्मा में छोड़ी गई परिसम्पत्तियों

3005. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या विदेश मंत्री विस्थापितों को बर्मा द्वारा दिए गए मुआवजे के बारे में 18 दिसम्बर, 1980 के अतः रांकित प्रश्न संख्या 4430 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उन सभी भारतीयों को बर्मा सरकार से मुआवजा दिलवाने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है जिनकी परिसम्पत्तियों का उस सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया है ;

(ख) क्या लम्बे अर्से से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए कोई विशेष प्रतिनिधिमंडल बर्मा भजा गया है या कोई अन्य कदम उठाया गया है ; और

(ग) क्या मैसर्स बर्मा माइन्स लिमिटेड को 1964 से (जब से भारतीयों की सम्पत्ति के साथ इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है) मुआवजा दिया जा रहा है और यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाएगी ?

विदेश मंत्री (श्री पी० बी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). हम इस मामले को अनौपचारिक तथा औपचारिक रूप से बर्मा सरकार को साथ उठाते रहे हैं। जनवरी, 1982 में बर्मा के विदेश कार्यालय ने लिखित रूप से यह बताया है कि सम्बन्धित प्राधिकारियों को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए पुनः अनुरोध किया गया है। यद्यपि हाल ही में किसी विशेष प्रतिनिधिमण्डल को बर्मा नहीं भेजा गया, लेकिन ऐसे भी सभी अनिर्णीत मामलों को उपयुक्त अवसरों पर क्या बर्मा प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। सरकार इस बात से अवगत है कि यू० के० की एक फर्म को कुछ मुआवजा दिया गया था, जिसकी सम्पत्ति को 1964 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारी हमेशा यह कोशिश रही है कि इस मामले को यथाशीघ्र हल किया जाए।

### Malpractices in Allotment of Haj Tickets

3006. SHRI H. N. NANJE GOWDA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether government attention has been invited to the news item appearing in Patriot dated 12th February, 1982 to the effect that serious malpractices are prevailing in the allotment of Haj Tickets;

(b) whether it is a fact that in some states like Jammu and Kashmir, legislators and some Government officials are given discretionary quota for the Haj seats;

(c) whether it is a fact that nearly 80 per cent of seats are decided at Bombay and the rest of 20 per cent in the state headquarters; and

(d) if so, the names of States whose applications are not being considered at the Headquarters and the prospec-